

424

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2011-12

एवं

वर्ष 2012-13

## लेखा परीक्षा प्रारूप

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप  
अनुच्छेद-1

423

क. सूचना पत्र

विभाग का नाम :- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
विभाग की संरचना :- प्रशासनिक ढांचा (संरचना) संलग्नक "क" पर  
क. स्वीकृत पदों की संख्या:- 63 पद  
ख. भरे गये पदों की संख्या:- 54 पद  
ग. बाह्यस्रोतिकरण द्वारा सेवायोजित कर्मचारियों का विस्तृत विवरण:- शून्य  
घ. दैनिक मजदूरों का विवरण, यदि कोई :- शून्य

विभागाध्यक्ष का नाम:- सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून  
ऑडिटी का विस्तृत विवरण उदाहरणार्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इत्यादि:-  
क. कार्यालयाध्यक्ष :- उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार

एवं

मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

प्रतिम लेखा-परीक्षाओं का विस्तृत विवरण (एजी तथा राज्य ऑडिट द्वारा सम्पादित, लम्बित पैराओं के विवरण सहित)

वर्ष	लेखा-परीक्षाण (एजी/राज्य लेखा-परीक्षा द्वारा)	महत्वपूर्ण अभियुक्ति	गैर महत्वपूर्ण बिन्दु	पैरा जिनके उत्तर दिये गये।	पैरा जिनके उत्तर नहीं दिये गये।	तत्संबन्धी आहूत ऑडिट कमेटी एवं निर्णय का विवरण	कुल लम्बित पैरा
107-08	राज्य लेखा-परीक्षा	00	01	01	00	-	01
108-09	राज्य लेखा-परीक्षा	00	01	01	00	-	01
109-10 से 10-11	राज्य लेखा-परीक्षा	00	07	07	00	-	07
11-12 से 12-13	राज्य लेखा-परीक्षा	00	26	26	00	-	26
योग		00	35	35	00	-	35

योजनाएँ/आयोजनागत व्यय के बजट विवरण:- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार का विगत 03  
वर्षों का स्वीकृत बजट एवं आय-व्यय का विवरण संलग्नक "ख" पर उपलब्ध है:-

योजनाओं का नाम /विवरण (केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फलैगशिप) योजनाएं) :- हरिद्वार-रूडकी विकास  
प्राधिकरण में कोई केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फलैगशिप) योजनाएं प्रचलित नहीं हैं अतः वांछित सूचना शून्य

योजनाओं का नाम /विवरण (केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फलैगशिप) योजनाएं) :- हरिद्वार-रूडकी विकास  
प्राधिकरण में कोई केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फलैगशिप) योजनाएं प्रचलित नहीं हैं अतः वांछित सूचना शून्य

रिसम्पत्तियों की स्थिति:- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में तैयार की गयी  
रिसम्पत्तियों का विवरण संलग्नक "ग" के अनुसार।

अन्य का विवरण :- प्राधिकरण में किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं है अतः वांछित सूचना शून्य है।

अनिल कुमार शर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

B

422

विभागीय प्राप्तियों का विवरण:- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य स्रोतों से किसी भी प्रकार के कोई अंशदान की प्राप्ति नहीं है अतः वांछित सूचना शून्य है।

वर्ष 2015-16

	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		अन्य (संस्था का नाम)	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 2016-17

	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		अन्य (संस्था का नाम)	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कय आदेश (पीओ) /दिये गये अनुबन्धों का विवरण

पीओ सं०	सामग्री/सेवा विवरण	पीओ/अनुबन्ध की तिथि	विक्रेता	राशि रू०.में	स्थिति(पूर्ण किया गया/ प्राकृत्याधीन)
1982	बोलेरो जीप ZLX 2WD 7STRBSIV	31.10.15	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि०. 202 द्वितीय तल के०-2 सोमदत्त टावर से०-18 नोयडा	7,16,463-00	पूर्ण किया गया
1992	बोलेरो कैम्पर PS 2WD BS4	02.11.15	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि०. 202 द्वितीय तल के०-2 सोमदत्त टावर से०-18 नोयडा	5,41,047-00	पूर्ण किया गया
721	इनोवा कार INNOVA CRYSTA 2.4 PACAKGE: X COLOR WHITE	21.07.2016	मैसर्स टोएटा किलोस्कर मोटर प्रा० लि०. 24 विठ्ठल माल्या रोड बैंगलोर	14,50,897-00	पूर्ण किया गया
3229	जनरेटर शाखा रूडकी शाखा ऋषिकेश	31.03.2016	मैसर्स गुप्ता इलैक्ट्रिक क०. रेलवे रोड हरिद्वार	5,07,285-00 4,56,212-00	पूर्ण किया गया
1018	ए०सी० (03नग)	08.09.2016	मैसर्स संत सेल्स, संत भवन आर्यनगर ज्वलापुर	85,950-00	पूर्ण किया गया
1444	अलमारी (12 नग)	02.11.2016	मैसर्स अग्रवाल फर्नीचर रूडकी हरिद्वार	77,288-00	पूर्ण किया गया

3. योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	.....के अधीन अनुमोदित योजना				अन्य	योजना लागत	प्रारम्भ तिथि	कार्यपूर्ति तिथि	भौतिक एवं वित्तीय तिथि
		जिला योजना	राज्य योजना	केन्द्रीय योजना	बाह्य					
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

4. तिथि को लम्बित ड्राफ्टों एवं चैकों का विवरण :- शून्य

5. असमायोजित अग्रियों का विवरण

- क. प्राईवेट पार्टियां :- शून्य
- ख. सरकारी सेवक :- शून्य

असिल कुमार शर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

01

16. बहुपक्षीय दानदाता/उधारदाता एजेन्सीयों (आईएमएफ/विश्व बैंक/एडीबी इत्यादि) के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापनों का विवरण।

क. निधीयन (फंडिंग) की राशि :- शून्य

ख. निधीयन (फंडिंग) की लागत :- शून्य

ग. उधारदाता एजेन्सी के प्रति वचनबद्धता और जिम्मेदारी :- शून्य

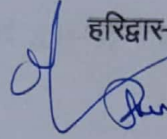
घ. परिपक्वता तिथि :- शून्य

ड. निधीयन (फंडिंग) के सदर्भ में कार्यान्वयन का सौपान :- शून्य

17. पीपीपी परियोजना का विवरण :- शून्य

संज्ञित,

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार



509  
421

प्रेषक,

निदेशक,  
लेखा परीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव,  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।



420

पत्रांक-389/नि0ले0प0(ऑ0)/2014-15

दिनांक: 10/10/2014

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0एस0नगन्याल)  
संयुक्त निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त/अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4. वित्त नियंत्रक, हरिद्वार, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
5. कार्यालय प्रति।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

दिनांक-

(एस0एस0नगन्याल)  
संयुक्त निदेशक।

2014  
Meve

A.O  
19/11/14

(1)

419

## हरिद्वार विकास प्राधिकरण

### लेखा परीक्षा टीम/पार्टी का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि हेतु लेखा परीक्षा	
लेखा परीक्षा टीम	
लेखा परीक्षा का प्रमुख	निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
टीम प्रभारी	डॉ० विजय लक्ष्मी, जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
टीम सदस्य	श्री गंगा सिंह रावत, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।
टीम सदस्य	श्री महीप कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

### लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार	
लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सचिव आवश्यक, उत्तराखण्ड शासन।
विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण हरिद्वार/आयुक्त गढ़वाल मण्डल
वित्त नियंत्रक	मुख्य वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
आहरण एवं वितरण अधिकारी	उपाध्यक्ष, सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
निदेशक लेखा परीक्षा उत्तराखण्ड	लेखा परीक्षा (ऑडिट) देहरादून, उत्तराखण्ड।

(2)

## अनुच्छेद-2

लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली/दृष्टिकोण (मुख्य विश्लेषण बिन्दु)

### बजट:-

- 1:- कुल प्रावधान की तुलना में कुल व्यय का अनुपात (रु० लाख में)- वर्ष 2011-12-18.78%  
वर्ष 2012-13-21.3
2. अनुपूरक बजट का उपयोग किया गया अथवा नहीं- अनुपूरक बजट नहीं बना था।
3. कुल प्रावधान के सापेक्ष समर्पित राशि- लागू नहीं
4. पुनर्विनियोग का विवरण और उस पर टिप्पणियां- पुनर्विनियोग नहीं किया गया था।
5. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित राशि और इसका उपयोग/निष्क्रिय- लागू नहीं।
6. यदि वेतन एवं भत्तों हेतु प्रावधान वास्तविकता आवश्यकता के अनुसार किया गया - हाँ।

### अधिप्राप्ति-

1. अवाई किए गए अनुबंधों/क्रय आदेशों का विवरण जहां अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लेख देखा गया- कोई नहीं।
2. प्रमुख अनावर्तक पूंजीगत मदों का विवरण जो जीर्ण-क्षीण/निष्क्रिय/काम करने की स्थिति में नहीं, के रूप में पड़ी है- कोई नहीं।
3. अनिस्तारित निष्प्रयोज्य मदों का विवरण- संस्था द्वारा अनिस्तारित निष्प्रयोज्य मदों से संबंधित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया।

### परियोजनाएं-

1. वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए वृहद निर्माण/अवस्थापना कार्यों हेतु परियोजना लागत/टाइम अलोकेशन का विवरण- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सूर्य ग्राम डालवाला में सामुदायिक केंद्र निर्माण कार्य भूस्वामित्व विवाद के कारण माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में निर्माण कार्य 2011 से लम्बित पाया गया।

(3)

2. प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के बिना प्रारंभ की गयी परियोजनाओं का विवरण- कोई नहीं।

418

3. पूर्ण किए बिना, रोकی गयी परियोजनाओं का विवरण और ऐसे निर्णय हेतु कारण-अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सूर्य ग्राम डालवाला में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य भू-स्वामित्व विवाद के कारण माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में परियोजना सम्बन्धी कार्यबन्ध (अनुच्छेद-3, आपत्ति क्रमांक-16)

4. निर्माण एजेन्सियों को अनियमित/अत्यधिक प्रतिशत प्रभारों (सेन्टेज चार्जेज) का विवरण- कोई नहीं।

#### योजनाओं का मूल्यांकन-

1. ध्वजवाही (फलैगशिप) योजनाओं के सम्बन्ध में योजना जनित सेवा, समयबद्धता और गुणवत्ता के संबंध में प्रश्नावली के लाभार्थियों से प्राप्त परिणाम- कोई नहीं।

2. ऐसी योजनाओं (सेवा क्षेत्र) का विवरण, जिनमें वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है- कोई नहीं।

3. विभिन्न योजनाओं हेतु आउट ले के सापेक्ष आउटपुट एवं आउटकम की स्थिति- कोई नहीं।

4. सब्सिडी की स्थिति- कोई नहीं।

5. नियोजित संसाधनों की मितव्ययिता और दक्षता के सापेक्ष मूल्यांकन (अप्रैजल)- कोई नहीं।

6. कार्यों अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त परिणाम स्थापित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप हैं तथा कि कार्य अथवा कार्यक्रम प्लानिंग के अनुसार निष्पादित किए जा रहे हैं।- कोई नहीं।



परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण-

1. सम्पत्तियों पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम और उनकी पर्याप्तता- प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों यथा आवासीय योजनाओं को सम्बन्धित स्थानीय निकाय/संस्था, को हस्तगत करा जाता है, तथा जो सम्पत्ति-स्थानीय निकाय अधिकार क्षेत्र से बाहर है अथवा किन्हीं कारणों से हस्तगत नहीं हो पायी हैं। उनके नियन्त्रण हेतु सम्पत्ति अधिकारी किया गया है।

2. निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए भौतिक सत्यापन का विवरण- भौतिक सत्यापन मार्च 2013 को किया गया।

3. शैल्फ आयु कालातीत होने के कारण प्रचलातीत सामग्री (इन्वेन्ट्री) का विवरण (दवाइयां, पाटर्स, उर्वरक, खाद इत्यादि)- कोई नहीं।

4. परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के उपायों की समीक्षा तथा उपयुक्तानुसार, ऐसी परिसम्पत्तियों की मौजूदगी का सत्यापन। प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सम्पत्तियां यथोचित पर्याप्त रूप से संरक्षित है तथा उनका समुचित प्रबंधन तथा लेखांकन किया गया है। परिसम्पत्तियों की सुरक्षा मात्र छोटी- मोटी चोरी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि खतरों जैसे कि पानी, बिजली इत्यादि संबंधी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए- प्राधिकरण सम्पत्ति के हेतु पर्याप्त उपाय किये गये थे। जिसमें अग्नि समन यंत्र, दीमक उपचार एवं सुरक्षा गार्ड कार्य उपलब्ध थे।

आंतरिक नियंत्रण- नियन्त्रण की मौजूदा प्रणाली, संगठन की स्थापना के अनुरूप है।

1. निर्धारित करना कि क्या नियंत्रण की मौजूदा प्रणाली संगठन की स्थापना से मेल खाती है। नियंत्रणों को जहां तक संभव है प्रचालन कार्यों (ऑपरेटिंग फंक्शन) के अंदर रखना एक प्रभावी उपाय के रूप में काम करता है- नियन्त्रण की मौजूदा प्रणाली संगठन की स्थापना के अनुरूप है।

2. प्रत्येक नियंत्रण की समीक्षा तथा लागत और लाभों के संदर्भ में विश्लेषण- नगर-नियंत्रण एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2009) द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित था, परन्तु सम्पत्ति नियन्त्रण से सम्बन्धी, सड़क पंजिका चार्ट तथा कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा जिसमें कार्य के दोहराव की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

वित्तीय विवरण-  
1. लेखा परीक्षा द्वारा आच्छादित समस्त क्षेत्रों में वित्तीय नियमों/पुस्तिका प्रावधानों के उल्लंघन

(5)

417

2. लेखा तैयार करने की स्थिति (समयबद्धता और अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0/नियामक निकाया जैसा लागू है)- सम्परीक्षा के समय संस्था का लेखा तैयार था।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों के अभिमतों का विश्लेषण, यदि कोई- - कोई नहीं।

4. लागू प्रावधानों के अनुसार टीडीसी कटौती तथा सांविधिक प्राधिकारों के साथ समयबद्धता के साथ भुगतानों की स्थिति जहां लागू है।- टी0डी0एम की कटौती कर यथासमय जमा किया गया था।

5. बैंक समाधान/कोषागार समाधान की स्थिति, पाए गए किसी गबन के विवरण सहित जहां लागू है।- बैंक समाधान विवरण बनाया गया था, गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।(अनु0सं0-03 की आपत्ति क्रमांक-22)

6. लम्बित न्यायालय वादों के संबंध में देयताओं का विवरण- देयताओं का विवरण कोई नहीं है।

7. निधियों का व्यावर्तन, की घटनाओं को उजागर करना यदि कोई- कोई नहीं।

क्रमशः वित्तीय विवरण-

8. निधियों/अलेखाबद्ध संभूत ब्याज की पार्किंग/अवरुद्ध करने की घटनाओं को उजागर करना-

9. अनुत्पादक व्ययों का विवरण- हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण पर आय व्यय किया गया था। (अनुच्छेद-03 के आपत्ति सं0-03) (6)

10. स्टाफ के अनावश्यक रखे जाने एवं सृजन का विवरण- अनुच्छेद-1(सूचना क्रमांक-02 के अनुसार

11. परिहार्य व्यय

12. उपकरणों/जीवन रक्षक उपकरणों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा

13. निष्क्रिय निवेश- कोई नहीं।

14. उन नीतियों, योजनाओं, प्रक्रियाओं, कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित स्थापित प्रणाली की समीक्षा करना, जिनका प्रचालन तथा प्रतिवेदनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और अवधारित करना चाहिए कि क्या संगठन अनुपालन में है।- संस्था का परिचय नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित-2009) के आधार पर किया जा रहा था।

9. अनुत्पादक व्ययों का विवरण- हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण पर व्यय किया गया था। (अनुच्छेद-03 के आपत्ति सं0-03)

10. स्टाफ के अनावश्यक रखे जाने एवं सृजन का विवरण- अनुच्छेद-1 (सूचना क्रमांक-02 के अनुसार

11. परिहार्य व्यय

12. उपकरणों/जीवन रक्षक उपकरणों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया

13. निष्क्रिय निवेश- कोई नहीं।

14. उन नीतियों, योजनाओं, प्रक्रियाओं, कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित  
स्थापित प्रणाली की समीक्षा करना, जिनका प्रचालन तथा प्रतिवेदनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव  
है और अवधारित करना चाहिए कि क्या संगठन अनुपालन में है।- संस्था का परि  
नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित-2009) के आधार पर किया जा रहा था।

## हरिद्वार विकास प्राधिकरण वर्ष 2011-12 एवं 2012-13

### आपत्ति क्रमांक- 1

स्वीकृत मानचित्र-पत्रावलियों पर भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न न होना:- आलोच्य सम्परीक्षा भवधि में आवासीय भवनो के प्रस्तुत स्वीकृत मानचित्र पत्रावलियों की जाँच करने पर पाया गया कि भू-खण्ड स्वामित्व वाले मानचित्र तो स्वीकृत किये गये थे परन्तु मानचित्र के साथ सम्बन्धित भूखण्ड के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे जिसमें सम्बन्धित स्वीकृत भू खण्डों के मानचित्र सम्बन्धी स्वामित्व का सत्यापन नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिये (i) माअ0/हरि0/एस0डब्लू0-215/2011-12 "श्रीमति रेनुका अरोडा पुत्री श्री के0एल0 बजाज निवासी प्लॉट नं0- 29, गुरु वक्स विहार आनन्दमई रोड कनखल, हरिद्वार, (ii) मान0/हरि0/एस0डब्लू0-233/2011-12, "श्री दिनेश कुमार एवं सतीश कुमार पुत्र श्री रामरतन प्लॉट नं0-64, द्वारिका विहार कालोनी ग्राम सुल्तानपुर माजरी परगना ज्वालापुर खसरा नं0-5, (iii) मान0 पत्रावली/म0यो0-1(क) मान0/हरि0/एम0 डब्लू0-60/12-13 "श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री पुलस्वय तिवारी प्लॉट नं0-18 द्वारिका विहार कालोनी सुलतानपुर माजरी, परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार, इत्यादि।

अतः स्थिति स्पष्ट कराते हुये इस प्रकार के समस्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- स्थिति स्पष्ट कराते हुये उपरोक्त प्रकार के समस्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वेमाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि स्वीकृत किये जाने हेतु मानचित्र पत्रावलियों पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भू-स्वामित्व की पुष्टि खसरा खतौनी/दाखिल खारिज की प्रति प्राप्त करके ही मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

### आपत्ति क्रमांक- 2

सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र पर सब डिविजन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति मानचित्र  
104243=00:- मानचित्र पत्रावलियों की जाँच करने से प्रकाश में आया कि, प्राधिकरण द्वारा सब डिविजन शुल्क सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्र फल पर न लेकर सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्र फल पर आगणित करते हुए वसूल किया गया था। उपविभाजन शुल्क नेट प्लॉट रिया पर लिये जाने सम्बन्धी नियम/शासनादेश सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, इस प्रकार सड़क

8

चौडीकरण क्षेत्र को कम करते हुए सबडिविजन शुल्क लिए जाने के फलस्वरूप  
में उपलब्ध प्रकरणों में निम्न विवरणानुसार ₹ 104243=00की क्षति हुई।

मानचित्र पत्रावली संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सड़क चौडीकरण क्षेत्र (वर्ग मी०)	शेष क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सड़क चौडीकरण उपविभाजन शुल्क की क्षेत्रफल×सर्किल रेट
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 63/2012-13	388.72	19.29	369.43	19.29×8700×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 65/2012-13	227.53	41.65	185.88	41.65×8700×3%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 43/2012-13	189.59	3.93	185.66	3.93×13850×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 50/2012-13	105.94	40.33	65.61	40.33×7490×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 75/2012-13	222.967	25.176	197.791	25.176×24600×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 56/2012-13	154.98	30.95	124.03	30.95×6200×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 55/2012-13	133.79	16.20	117.59	16.20×11500×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 58/2012-13	269.96	3.54	266.42	3.54×10,000×3%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 231/2011-12	332.02	77.69	254.33	77.69×6800×3%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 230/2011-12	193.30	14.14	179.16	14.14×5350×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 77/2012-13	139.37	19.87	119.50	19.87×9100×1%
मान०/हरि०/एस०डब्लू०- 78/2012-13	278.59	59.23	219.36	59.23×7300×1%
मान०/हरि०/आर०एस०- 10/36/2012-13	1522.85	167.23	1355.62	167.23×167250×2%

लेखा परीक्षा संस्तुति:- आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

योग:-

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि रोड वाईडनिंग क्षेत्र  
द्वारा किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है अतः उप  
उपविभाजन शुल्क भी नहीं लिया जाता है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

09

415

संख्या

आपत्ति क्रमांक- 3

हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय ₹ 1062108=00:- भुगतान एवं प्राप्ति विवरणों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में हरिलोक आवासीय कालोनी के अनुरक्षण पर प्राधिकरण द्वारा ₹ 13,59,076=00 व्यय किया गया था जबकि अनुरक्षण मद में आय मात्र ₹ 6,05,639=00 हुई। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में हरिलोक अनुरक्षण पर व्यय ₹ 9,98,681=00 के सापेक्ष मात्र ₹ 6,90,010=00 आय हुई। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-7 के अनुसार आवासीय कालोनी का अनुरक्षण करना प्राधिकरण के उद्देश्यों/कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं था। अतः प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः ₹ 7,53,437=00 तथा ₹ 3,08,671=00 की क्षति हुई जो प्राधिकरण के हितों के प्रतिकूल था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- चूंकि हरिलोक कालोनी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है अतः इसे हस्तान्तरण करना सम्भव नहीं है। परन्तु हरिलोक कालोनी का अनुरक्षण शुल्क की आय बढ़ाये जाने हेतु मांग आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 4

अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय/आवास की रंगई पुताई आदि पर अनियमित व्यय रुपये 88,972=00:- चैक सं0 "686595" दिनांक 04.08.2012 द्वारा के अध्यक्ष/आयुक्त गढवाल मण्डल के कैम्प कार्यालय/आवास की रंगई पुताई आदि हेतु मै0 अब्दुला लतीफ ठेकेदार पौड़ी गढवाल को निम्न बिलों के सापेक्ष आयकर कटौती उपरान्त ₹ 83,632=00 भुगतान किया गया था।

बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1374	14.05.2012	14040
1320	15.05.2012	14960
1322	16.05.2012	14960
1326	17.05.2012	10640
1330	18.05.2012	11400
1328	21.05.2012	14972
1331	22.05.2012	8000
	योग	₹ 88972

उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी:-

1. कोई कार्यादेश निर्गत नहीं था।
2. कोई प्रावलन तैयार नहीं कराया गया था।
3. कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं थे।
4. कुल कार्य के सापेक्ष टुकड़ों में विभाजित कर बिल प्राप्त किये गये थे।
5. वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृत उपलब्ध नहीं थी।
6. बिलो पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित नहीं थी।
7. बिल सं० 1320 पर दिनांक 15.05.2012 जबकि पश्यातवर्ती बिल संख्या 1324 पर 14.05.2012 अंकित थी।
8. कार्य की मापें उपलब्ध नहीं थी।
9. अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय समिति का प्रमाण पत्र अंकित नहीं था।

इसके अतिरिक्त आयुक्त आवास/कैम्प कार्यालय राज्य सम्पत्ति विभाग के भवन में आवस्थित था जिसके अनुरक्षण/रंगाई पुताई का जिम्मा राज्य सम्पत्ति विभाग अतः उपरोक्त भुगतान पूर्णतः अनियमित था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग से करा अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि अध्यक्ष/आयुक्त कार्यालय बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु भेजे गये जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया है। अभिलेख अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय में उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 5

विलम्ब दण्ड की वसूली न किया जाना:- चैक सं० "731212" दिनांक 27.12.2012 द्वारा आदि शिव कंस्ट्रक्शन को अनुबन्ध सं० 21/2006-07 इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग मीटर मार्ग के बाद हिन्दुस्तान लीवर के और सड़क व नाली निर्माण कार्य के पंचम ए देयक का रू० 9,67,773=24 भुगतान किया गया था।

पत्रावली में नोट शीट सं० 31 पर अवर अभियन्ता की टिप्पणी के क्रम में कार्यालय 1261/अमि० 1(क)-44/2006-07 दिनांक 18.07.2011 द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 2011 तक की समय वृद्धि प्रदान करते हुए यह भी अवगत कराया गया कि कार्य अतिरिक्त समय वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त पत्र के बाद दिनांक 13.09.2012 तक पत्रावली के कोई टिप्पणी अंकित न कार्य पूर्ण किया गया अथवा नहीं।



(11)

414

पत्रावली नोट शीट सं० 36 पर निर्गत लिपिक द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत अन्तिम तिथि 31.08.2011 नियत थी अतः कार्य की औपचारिक समय वृद्धि तिथि नियत करते हुए स्वीकृति अपेक्षित है" अंकित किया गया जिसके क्रम में सहायक अभियन्ता द्वारा "कार्य दिनांक 31.08.2011 को पूर्ण किया जा चुका है" अंकित किया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने की कोई सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं पायी गयी, न ही प्राधिकरण की ओर से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

कार्य की मापें-माप पुस्तिका सं० 101(2) के पृष्ठ सं० 1 से 93 पर अंकित थी। कार्य की मापे भी पृष्ठ 87 पर दिनांक 13.07.2011 के उपरान्त लगभग डेढ़ वर्ष के अन्तराल के बाद दिनांक 12.12.2012 को अंकित करते हुए पंचम एवं अन्तिम देयक तैयार किया गया था जिसके सापेक्ष उपरोक्तानुसार भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि माप पुस्तिका में अंकित मापे प्रथम रनिंग बिल के उपरान्त कभी भी सहायक अभियन्ता द्वारा जांच नहीं की गयी थी।

यदि कार्य 31.08.2011 को पूर्ण किया जा चुका था तो कार्य की माप लगभग डेढ़ वर्ष उपरान्त दिनांक 12.12.2012 को अंकित किये जाने का औचित्य नहीं था।

अतः किसी भी प्रकार कार्य 31.08.2011 तक पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है। माप पुस्तिका में माप की तिथि 12.12.2012 को कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि मानते हुए कार्य में हुए विलम्ब हेतु अनुपलब्ध के प्रावधानानुसार लागत मूल्य के 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से जमा जमानत राशि की अधिकतम सीमा तक दण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था। परन्तु प्राधिकरण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना विलम्ब दण्ड के भुगतान कर दिया गया। विलम्ब दण्ड के अधिकतम ₹ 4,94,008=00 (जमानत राशि) की वसूली अपेक्षित है।

विदित है कि कार्य मद सं० 1/1 अर्थवर्क कुल कार्य 5143.63 घनमीटर कार्य हेतु रुपये 155/प्रतिघन मीटर की दर से 7,97,262=65 + 3% (टैण्डर दर) = ₹ 8,21,180=53 भुगतान किया गया था जिसमें से नियमानुसार 12.50 प्रतिशत कम्पैक्शन की कटौती नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप ₹ 1,02,647=57 का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्तानुसार वसूली अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता की आख्यानानुसार कार्य स्वीकृत तिथि के अन्दर ही पूर्ण किया जा चुका था। अतः विलम्ब दण्ड वसूली योग्य नहीं था।

अर्थ वर्क की मापें कम्पैक्शन को छोड़कर ही अंकित की गयी थी अतः पृथक से कम्पैक्शन हेतु कटौती नहीं की गयी है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

10/10/20

आपत्ति क्रमांक- 6

मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति ₹ 10,495=00 संख्या 4697 श0वि0-आ0-2004-80 (सा)/2003 दिनांक 19.10.04 द्वारा विकास भवन मानचित्र से सम्बन्धित शुल्को का निर्धारण किया गया था। उपर्युक्त शासन परिशिष्ट के क्रमांक 1(1-1) (क) में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवन क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर तक ₹ 100=00, 101 से 200 वर्गमीटर तक ₹ 200=00, 201 से 300 वर्गमीटर तक ₹ 300=00 तथा उसके पश्चात ₹ 2=00 प्रति वर्गमीटर की दर से पर जो भी अधिक हो" के अनुसार मानचित्र आवेदन शुल्क का प्रावधान किया गया मानचित्र पंजिका की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 300 वर्ग मीटर से वाले प्रकरणों में निर्धारित ₹ 2 प्रति वर्गमीटर की दर से न लेकर कम आवेदन शुल्क था जिससे प्राधिकरण को निम्न विवरणानुसार ₹ 10,495=00 की आर्थिक क्षति हुई।

मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिया जाना

मानचित्र पत्रावली संख्या	नाम	मुखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्राप्य आवेदन शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क
500-04/11-12	प्रकाश चन्द शर्मा	341.41	684	419-35 =384
500-12/11-12	बलवन्त सिंह	305.25	612	348-35 =313
500-14/11-12	हेम चन्द	398.18	798	515-35 =480
500-29/11-12	पूनम	305.76	612	348-35 =313
500-30/11-12	चंचल	306.48	614	350-35 =315
500-42/11-12	विक्रम सिंह	325.87	652	387-35 =352
500-57/11-12	स्वामी ओमानन्द	655.50	1312	1048-35 =1013
500-59/11-12	पर्ल इंस्टीट्यूट	418.21	838	575-35 =540
500-87/11-12	सुनील कुमार गुप्ता	435.59	872	872
500-133/11-12	दीपक अरोडा	369.86	740	475-35 =440
500-166/11-12	माता सुनीता देवी शक्ति संस्थान	443.87	888	623-35 =588
500-181/11-12	मनोज गुप्ता	400.89	802	535-35 =502
500-186/11-12	प्रदीप जैन	539.98	1080	815-35 =780
500-222/11-12	नारायण दास	408.24	818	555-35 =520
500-240/11-12	सुनील अग्रवाल	314.27	630	364-35 =329
500-241/11-12	---	308.55	618	352-35 =317

₹ 10,495=00:- शासनादेश द्वारा विकास प्राधिकरण पर्युक्त शासनादेश में आवासीय भवनों हेतु ₹ 200=00, 201 की दर से या उससे अधिक मीटर से अधिक म आवेदन शुल्क लिए जायेंगे।  
प्राप्त आवेदन शुल्क

500-14/12-13	राजीव बंसल	330.16	662	398-35	299
500-41/12-13	सुनैना	342.52	686	=363	
500-57/12-13	ओम प्रकाश	786.21	1574	421-35	300
500-59/12-13	कुसुम लता	457.38	916	=386	
500-63/12-13	सुशीला देवी	369.43	740	1307-35	302
500-70/12-13	बृजनाथ	399.76	800	=1272	
500-91/12-13	गौतम कुमार वर्मन	483.25	968	640-35	301
500-109/12-13	राजीव बंसल	689.29	1380	=615	
500-132/12-13	पुष्पा देवी	327.60	656	465-35	310
500-170/12-13	श्री भगवान देव	474.88	950	=430	
500-180/12-13	योगाश्रम ट्रस्ट	385.32	772	535-35	300
500-187/12-13	म0 राम नारायण गिरि	315.88	632	=500	
500-188/12-13	श्री नारायण पुरी	327.29	656	703-35	300
500-236/12-13	श्री तुषार शर्मा	315.00	630	=668	
500-248/12-13	गीता पोली	495.52	992	1115-35	300
500-257/12-13	राम जी भाई	631.26	1264	=1080	
500-258/12-13	निशान्त गोयल	949.76	1900	391-35	300
500-259/12-13	अम्बा जी	339.86	680	=356	
500-274/12-13	बेली राम कुमार	304.84	610	685-35	300
500-312/12-13	नीरज कुमार	552.30	1106	=650	
	सुभाष गुप्ता			472	300
				367-35	300
				=332	
				391-35	300
				=356	
				365-35	300
				=330	
				750-35	277
				=715	
				1000-35	299
				=965	
				1635-35	300
				=1600	
				417-35	298
				=382	
				345-35	300
				=310	
				842-35	299
				=807	
				<u>योग:- ₹ 10,495</u>	

लेखा परीक्षा संस्तुति:- आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 4697, दिनांक 19.10.2004 में 300 वर्गमी0 तक रू0. 300-00 तथा उसके पश्चात रू0. 2-00 प्रति वर्गमी0 की दर निर्धारित है तदनुसार ही आवेदन शुल्क लिया गया।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 7

सन्तुष्टि

हरिलोक अनुरक्षण शुल्क की राशि विलम्ब से जमा किया जाना:- रसीद संख्या 626/13 दिनांक 19.03.2012 एवं 20.03.2012 द्वारा हरिलोक अनुरक्षण शुल्क क्रमशः ₹ 828=00 प्राप्त थे। उक्त धनराशि की दिनांक 29.03.2012 को रोकड़ बही में गया था। विलम्ब से जमा का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।  
लेखा परीक्षा संस्तुति:- विलम्ब से जमा का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अवकाश पर होने के कारण विलम्ब हुआ। भविष्य में ऐसा न किये जाने हेतु सम्बन्धित को सचेत कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 8

अभिमत

सब स्टैण्डर्ड कार्य हेतु दण्ड आरोपित न किया जाना:- बैंक सं० "731574" दिनांक 02 द्वारा भूपतवाला रानीगली मार्ग के अन्तरिक सड़कों का सुदृडीकरण कार्य के तृतीय/अंतिम का श्री नरेन्द्र कुमार ठेकेदार को ₹ 6,02,283=00 भुगतान किया गया था। पत्रावली जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण पत्रांक 1396 दि० 29.07.2011 द्वारा भेजे गये सैटेस्टिंग के क्रम में कार्यलय शोध अधिकारी, मृतिका खण्ड-2 सिंचाई अनुबंधान संस्था की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट की मात्रा कम प्रयुक्त किये जाये पर नोट पर अंकित गणनानुसार कम लगाये गये सीमेन्ट के मूल्य ₹ 2,29,429=30 की कटौती की सीमेन्ट मूल्य की कटौती किया जाना उचित था। परन्तु ठेकेदार द्वारा म विपरीत कार्य किया गया जिससे कृत कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी, इस हेतु सीमेन्ट अतिरिक्त कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी अर्थात् उतनी ही धनराशि की कटौती जितना मूल्य का सीमेन्ट ठेकेदार द्वारा अनियमित रूप से बचाया गया था।

2- इसी प्रकार बैंक सं० "744798" दिनांक 11.01.2012 द्वारा तपोवन बद्रीनाथ मार्ग गढ़वाल में विभिन्न सी०पी० सड़कों का निर्माण कार्य हेतु II & final bill के सापेक्ष श्री पोखरियाल ठेकेदार को ₹ 6,09,267=65 का भुगतान किया गया था। इसमें भी टेस्टिंग आधार पर कम प्रयुक्त सीमेन्ट की गणना कर सीमेन्ट मूल्य ₹ 16,060=00 की कटौती थी। गुणवत्ता प्रभावित करते हुए मानको के विपरीत निर्माण कार्य हेतु कोई दण्डात्मक नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी0डब्लू0डी0मानको के अनुसार कार्यो को स्वीकृत करते हुए आवश्यक कटौती उपरान्त ही भुगतान किया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 9

भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जाना:- भवन अग्रिम पंजिका की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री मामचन्द, अवर अभियन्ता को 18.12.1991 को प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम ₹ 50,000=00 के सापेक्ष माह मार्च, 2000 के उपरान्त कोई वसूली नहीं की गई थी। आलोच्य अवधि के अन्त में श्री मामचन्द पर उक्त अग्रिम का ₹ 11,976 तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अधावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

इसी प्रकार श्री राजीव, सहा0 अभियन्ता से वर्ष 1995-96 में प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम ₹ 1,40,000 के सापेक्ष माह जून, 2005 के पश्चात कोई वसूली नहीं की गयी थी। श्री अधिकारी पर ₹ 1472 मूलधन तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अधावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनो कर्मचारी अधिकारी अन्यथा विकास प्राधिकरणों हेतु कार्यमुक्त किये जा चुके थे।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त अग्रिमों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भवन निर्माण अग्रिमों की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 10

विना खाता खतौती भू स्वामित्व की पुष्टि अनियमित:-

1-मानचित्र सं0- मान/हरि/S.W-38/2011-12 दिनांक 15.06.2011 की पत्रावली जांच करते समय पाया गया कि उक्त पारित नक्शा में भूस्वामित्व प्राधिकरण अधिवक्ता की आख्या/राय के अनुसार प्रमाणित था। मानचित्रकार द्वारा प्राधिकरण अधिवक्ता से भू स्वामित्व आख्या चाही गयी थी।

मानचित्र

(16)  
मानचित्र पारण में भू स्वामित्व आख्या के लिये अधिवक्ता को पत्रावली किन अन्तर्गत दी गयी थी स्पष्ट नहीं था। प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में आख्या राय दी गयी थी और उक्त राय को अवर अभियंता द्वारा आख्या मानते हुये भू स्वामित्व माना गया था। विक्रय विलेख (बैनामा) के साथ खसरा खतौनी/दाखिल खारिज पत्र उपलब्ध नहीं था।

2- इसी प्रकार पत्रावली मान0/हरि0/S.W-227/2011-12 श्रीमति रेखा शर्मा मी0 हरिद्वार में भी प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा स्वामित्व की पुष्टि रजिस्ट्री/विक्रयविलेख के अ की गयी थी।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- भूस्वामित्व की पुष्टि हेतु खसरा खतौनी/दाखिल खारिज की पु किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि स्वीकृत किये जाने हेतु पत्रावलियों पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भू-स्वामित्व की पुष्टि खतौनी/दाखिल खारिज की प्रति प्राप्त करके ही मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 11

सबडिविजन शुल्क कम लिया जाना:- रसीद सं0 627/92 दिनांक 12.03.2012 /हरि0/500-220/2011-12 के सापेक्ष श्रीमति चारु मेहता, न्यू हरिद्वार ग्राम-अहमदपुर कडच्छ ज्वालापुर, हरिद्वार से कुल ₹ 31,590=00 प्राप्त था। जिसमें अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 178.36 वर्ग मी0 द0 सर्किल रेट 11,100=00 प्रति0वर्ग0मी0 प्रतिशत की दर से ₹ 19,798=00 सबडिविजन शुल्क लिया गया था। संलग्न दिवस अनुसार दो तरफ रास्ता होने के कारण भूमिदर का 10 प्रतिशत अधिक अर्थात् सर्किल 12,210=00 प्रति वर्ग मीटर थी। इस प्रकार 12,210-11100=1110 का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ग मीटर की दर से 178.36 वर्ग मी0 ₹ 1979.80 सबडिविजन शुल्क कम लिया प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- कम लिये गए शुल्क की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि कम सबडिविजन शुल्क की सम्बन्धित आवेदक से करा ली जायेगी।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 12

विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी न किया जाना:- आलोच्य वर्षों में प्राप्ति एवं भुगतान विवरण के अनुसार क्रमशः ₹ 14,92,436=00 तथा ₹ 12,67,872=00 का भुगतान विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के विविध विज्ञापनों हेतु किया गया था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्राप्त विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से निर्गत न करके सीधे निर्गत किये गये थे। जो सूचना अनुभाग के शासनादेश संख्या 75/प्र0स0सू0/2009 दिनांक 09.10.2009 तथा 452/xxii/2011-(2)2008 दिनांक 21.11.11 का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण के विज्ञापन इस आशय से प्रकाशन न किये जाने हेतु वापस किये गये हैं कि प्राधिकरण स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आता है जिनके विज्ञापन बाजार मूल्य पर प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए विज्ञापन प्राधिकरण स्तर से ही प्रकाशित कराये जाते हैं।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 13

उत्तर

शमन मानचित्र निर्गत न किया जाना:- पत्रावली संख्या नो0 ज्वा0/399/06-07 की जाँच में पाया गया कि श्रीमति बीना शर्मा, पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा के शमन आदेश पत्र दिनांक संनिकित के क्रम में प्राधिकरण पत्रांक -मीमो/नो0/ज्वालापुर/399/06-07 दिनांक 2.04.2009 द्वारा शमन शुल्क गणना करते हुए ₹ 43,123=00 जमा कराने तथा शमन मानचित्र में पीले रंग से दर्शाये गये अशमनीय निर्माण के स्वयं ध्वस्त किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। बिल संख्या- 26/637 दिनांक 26.06.2012 ₹ 25,179=00, 55/636 दिनांक 16.06.2012 ₹ 27,000=00, तथा 69/661 दिनांक 09.04.2013 ₹ 11,000=00 ब्याज सहित शमन शुल्क जमा था परन्तु अशमनीय निर्माण को तोड़े जाने के सम्बन्ध में न तो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था न ही तोड़े जाने का कोई अन्य विवण अथवा प्राधिकरण प्रमोचारी/अधिकारी की कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध थी। सम्परीक्षा तिथि तक शमन मानचित्र निर्गत नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुए मानचित्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही शमन मानचित्र निर्गत कर दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

विधि

आपत्ति क्रमांक- 14

परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की धनराशि प्राप्त न किया जाना:- प्राधिकरण को वर्ष 2008 में निर्णीत वादो से सम्बन्धित राशि मात्र ₹ 43,000=00 रसीद सं० 78/662/दिनांक 2013 द्वारा प्राप्त थी।

आलोच्य अवधि में सी०जे०एम० कोर्ट हरिद्वार द्वारा विभिन्न परिवादों में हरिद्वार प्राधिकरण के पक्ष में ₹ 3,28,000=00 परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने के आदेश पारित थे।

जिसे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त गत विगत वर्षों की अप्राप्त प्राप्त किये जाने हेतु भी कार्यवाही अपेक्षित है।

टिप्पणी:- विगत वर्षों में प्राधिकरण के पक्ष में परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने सम्बन्धी कोर्ट अनुरक्षित नहीं की गयी थी जिस कारण कुल अर्थदण्ड की धनराशि स्पष्ट नहीं हो पायी। पंजिका अनुरक्षित करते हुए अर्थदण्ड का कववरण भी अंकित किया जाना अपेक्षित है।  
लेखा परीक्षा संस्तुति:- जुर्माने की अप्राप्त धनराशि को प्राप्त किए जाने हेतु प्रभावी किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की धनराशि को प्राप्त हेतु प्रयास किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

विधि

आपत्ति क्रमांक- 15

पार्किंग स्थल की अनुपलब्धता पर शमन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आदि  
₹ 69,89,112=00:- रसीद संख्या 29/606 दिनांक 22.06.11, 48/609 दिनांक 88/619 दिनांक 15.12.2011, 55/637 दिनांक 29.06.2012, 94/640 दिनांक 01.08.2012/641 दिनांक 06.08.2012 द्वारा पत्रावली संख्या- नो०/ज्वा०/126/2002-03 क्लासिक रेजीडेन्सी हरिद्वार से शमन शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 2,00,000, ₹ 200000, ₹ 1500000 तथा ₹ 16,535=00 कुल ₹ 23,16,535=00 पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण के नोटिस संख्या- नो०/ज्वा०/126/2002 दिनांक 14.06.2002 के क्रम में प्रबन्धक होटल क्लासिक रेजीडेन्सी हरिद्वार के शमन आदि दिनांक 29.05.2007 पर कार्यवाही करते हुए नोट सीट संख्या 23 से 28 पर शमन



19

410

गणना कराने हेतु पत्र संख्या 4809 दिनांक 04.03.2009 प्रेषित किया गया था। होटल क्लासिक रेजीडेन्सी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2009 के बिन्दु संख्या 6 में पूर्व में दिनांक 02.02.1988 को स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग प्रावधान न होने के कारण पार्किंग शमन शुल्क न लगाने की प्रार्थना पर पत्रावली नोटशीट संख्या 36 पर सहायक अभियन्ता द्वारा प्राधिकरण सचिव एवं उपाध्यक्ष से विचार विमर्श के पश्चात, पार्किंग शमन शुल्क आरोपित न किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया जिसके क्रम में नोटशीट संख्या 37 से 41 पर पूर्व में आंगणित पार्किंग शमन शुल्क ₹ 69,89,112=00 को छोड़ते हुए तथा अन्य मदों में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः कुल शमन शुल्क ₹ 23,16,535=00 आंगणित करते हुए पत्रांक 3430 दिनांक 09.03.2010 द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में उपरोक्तानुसार धनराशि प्राप्त थी।

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 1996 के अनुसार पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुणा शमन शुल्क के रूप में देय था। इसी आधार पर नोटसीट सं० 23 से 28 पर शमन शुल्क की गणना की गयी थी। प्राधिकरण की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 यथा संशोधित 2004 एवं 2007 के नियम 1.3 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 उत्तराखण्ड के नियम 1.2.1 के अनुसार उक्त उपविधियों के प्रावधान भवन के निर्माण के साथ-साथ पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन पर भी लागू थे। उपरोक्त उपविधियों में क्रमशः नियम 3.10 तथा 2.1.3 में पार्किंग हेतु प्रावधान किये गये थे जो उपरोक्त नियम 1.3 तथा 1.2.1 के अनुसार पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन की दशा में भी लागू थे। होटल क्लासिक रेजीडेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.09 के प्रस्तर 1 व 4 से स्पष्ट था परिवर्द्धन (addition) किया गया है अतः पार्किंग शमन शुल्क आरोपित न किये जाना पूर्णतः अनियमित एवं आपत्तिजनक था जिसमें फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 69,89,112=0 की अर्थिक क्षति हुई। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में तत्समय लागू भवन उपविधियों के अनुसार पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं था उसी आधार पर वर्तमान में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पार्किंग शमन शुल्क न लिये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 16

प्राधिकरण निधि का दुरुपयोग ₹ 24,10,016=00:- अवस्थापना विकास समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सूर्यग्राम ढालवाला में सामुदायिक निर्माण का ठेका श्री इकबाल अहमद ठेकेदार के नाम स्वीकृत था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्थल के भू स्वामित्व की पुष्टि नहीं करायी गयी। भू स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रधान, ग्राम पंचायत ढालवाला, विकास खण्ड-नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल में पत्र

अभिमत

दिनांक 08.09.2006 तथा उपजिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर के पत्र संख्या-मैमो/अ/अ  
दिनांक 28.09.2006 (पत्र में 2006 के स्थान पर 3006 अंकित) को आधार लेते हुए  
समाज का मान लिया गया। राजस्व अभिलेखों से खसरा खतौनी/फरहद की प्रति  
गयी।

भू-स्वामित्व की पुष्टि कराये बिना ही दिनांक 08.04.2011 के निविदा आमंत्रण  
का ठेका श्री इकबाल अहमद ठेकेदार के नाम स्वीकृत करते हुए पत्रांक 923/अ/अ  
43/2007-08 दिनांक 17.06.2011 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। उक्त कार्यादेश  
ठेकेदार द्वारा स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

श्रीमति आशा सरन द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन  
देहरादून में उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी व्यक्त करते हुए प्राधिकरण के विरुद्ध  
17/1012 दायर किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक  
द्वारा वाद ग्रस्त सम्पत्ति पर निर्माण करने से प्राधिकरण को निषिद्ध किया गया। उक्त  
विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा मानवीय जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून में अपील सं0 82  
गयी जिस पर दिनांक 28.05.2012 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थल पर फिनिश  
अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य न किये जाने के आदेश पारित किये गये। तत्क्रम में स्थल  
बन्द करा दिया गया तथा निम्न विवरणानुसार कुल कृत कार्य 24,10,016.27 के सा  
को भुगतान कर दिया गया।

<u>चैक संख्या</u>	<u>दिनांक</u>	<u>धनराशि</u>	<u>विवरण</u>
745032	23.1.12	7,39,817=83	प्रथम रनिंग बिल
685833	07.05.2012	12,64,790=00	द्वितीय रनिंग बिल
731267	22.01.2013	1,85,118=29	तृतीय रनिंग बिल

इसके अतिरिक्त पत्रावली प्रथम के नोट सीट सं0 20 पर अंकित अवर  
टिप्पणी दिनांक 08.12.2009 के अनुसार उक्त स्थल का महायोजना में भू उपभोग बी-  
निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत था जिसमें सामुदायिक केन्द्र निर्माण अनुमत्य नहीं था तथा भू-  
में सामुदायिक केन्द्र हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर से कम  
स्थल भवन उपविधि की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता था।

उपरोक्त से स्पष्ट था कि प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण उप  
विपरीत बिना भूस्वामित्व की पुष्टि किये ही कराया जा रहा था जिस पर ₹ 24,10,016.27  
भुगतान कर प्राधिकरण निधि का दुरुपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- दुरुपयोग के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए  
कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि भू-स्वामित्व की पुष्टि  
पचायत डालवाला एवं उपजिलाधिकारी नरेन्द्र नगर से प्राप्त आवश्यक प्रमाण पत्र एवं  
होने के उपरान्त ही कार्य कराया गया था।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 (ग्रुप हाउसिंग):- प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग में 48-01 रूम फ्लैट दुर्बल आय वर्ग हेतु तथा 96-2बी0एच0के0 फ्लैट की परियोजना तैयार कर वर्ष 2011-12 में फ्लैटों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

आवेदन पत्र की शर्तों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग हेतु 01 रूम फ्लैट का अनुमानित मूल्य ₹ 6,95,000=00 निर्धारित था। भुगतान की शर्तों के अनुसार नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आवेदन के साथ 25 प्रतिशत आवन्टन पर तथा आवन्टन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर शेष 65 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जानी है, किश्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत शेष 65 प्रतिशत धनराशि 80 समान तिमाही किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित भुगतान किया जाना था।

दुर्बल आय वर्ग के आवेदको हेतु अधिकतम मासिक आय ₹ 5000=00 अर्थात् ₹ 60000=00 वार्षिक निर्धारित थी। शेष 65 प्रतिशत राशि पर 12 प्रतिशत व्याज सहित 80 तिमाही किश्तों की गणना पर प्रति किश्त ₹ 14958=00 आती है। इस प्रकार आबन्टी को प्रतिमाह 14958/3 ₹ 4,986=00 अथवा प्रतिवर्ष ₹ 59,832=00 किश्त के रूप में जमा कराना है। जिस व्यक्ति की समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय ₹ 5000=00 प्रतिमाह या ₹ 60,000=00 प्रतिवर्ष हो, वह किस प्रकार किश्त जमा करायेगा, यह योजना की सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह है। स्पष्ट है कि परियोजना निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाई गई थी। उदाहरण स्वरूप:-

1- रसीद सं० 36/635 दिनांक 05.06.2012 द्वारा श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री ओमवीर सिंह से दुर्बल आयवर्ग आवासीय योजना इन्द्रलोक में एक रूम फ्लैट अनुमानित मूल्य ₹ 6,95,000=00 के आवन्टन के सापेक्ष आबन्टन राशि ₹ 1,73,750=00 प्राप्त थे। कार्यलय पत्रांक 257/सम्पत्ति/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट इन्द्रलोक योजना/2011-12 दिनांक 27.04.2012 द्वारा अनुमानित मूल्य ₹ 6,95,000=00 की अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि को ₹ 4,51,750=00 को 12 प्रतिशत व्याज सहित 80 समान तिमाही किश्तों में प्रति किश्त ₹ 14,958=00 जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित था। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र तथा संलग्न अन्य प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी की आय ₹ 50,000=00 प्रति वर्ष थी। ऐसे में प्रार्थी के द्वारा तिमाही किश्त के रूप में ₹ 14,958=00 किस प्रकार जमा कराया जायेगा ?

2- इसी प्रकार रसीद सं० 58/636 दिनांक 18.06.2012 द्वारा श्रीमती सुषमा शर्मा से आवन्टन राशि ₹ 1,73,750=00 प्राप्त थी। शेष 65 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत व्याज सहित 80 समान तिमाही किश्तों में ₹ 14,958=00 जमा कराई जानी थी। प्रार्थी के आय प्रमाण पत्र के अनुसार आय ₹ 4000=00 प्रतिमाह अर्थात् ₹ 48,000=00 प्रतिवर्ष थी।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- योजना का पुर्नमूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रस्ताव प्राधिकरण की 56 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 में प्रस्ताव रखा गया जिसमें चर्चा न होने के कारण आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 18

बेचे गये भूखण्डों के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार न लिए जाने के फलस्वरूप  
 ₹ 2,46,93,154=00:- आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय  
 152/9-आ-1-1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 के प्रस्तर-5(छ) में विकास प्राधिकरण  
 जाने वाले भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने तथा उक्त  
 शत-प्रतिशत राशि को अवस्थापना विकास निधि में जमा किये जाने के निर्देश पारित  
 हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना तथा ट्रांसपोर्ट नगर  
 अन्तर्गत सम्परीक्षा तिथि माह जून, 2013 तक विक्रय किये गये क्रमशः 498 तथा 60  
 उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत अधिभार वसूल नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप प्रा  
 निम्न विवरणानुसार ₹ 2,46,93,154=00 की आर्थिक क्षति हुई:-

योजना का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्डों की संख्या	दर	कुल
इन्द्रलोक आवासीय योजना	एच0आई0जी0ए0 300 वर्ग मी0 —तदैव—	03	14,10,000=00	42.3
	—तदैव—	30	8,10,000=00	2,43,00
	एच0आई0जी0बी0 250 वर्ग मी0 —तदैव—	01 04	23,51,100=00 11,75,000=00	23.5 47.0
	एच0आई0जी0सी0 200 वर्ग मी0	22 39	6,75,000=00 5,40,000=00	1,48,50 2,10,60
	एच0आई0जी0डी0 162 वर्ग मी0	122	4,37,400=00	5,33,62
	एम0आई0जी0—ए0 120 वर्ग मी0 —तदैव—	21	5,64,000=00	1,18,44
	—तदैव—	90	3,24,000=00	2,91,60
	एम0आई0जी0—बी0 90 वर्ग मी0 —तदैव—	01 02	9,40,440=00 4,23,000=00	9.40 8.46
	एल0आई0जी0 72 वर्ग मी0 —तदैव—	65 34	2,43,000=00 3,38,400=00	1,57,95 1,15,05
	—तदैव—	63	1,94,400=00	1,22,47
	गोदाम हेतु भूखण्ड 875 वर्गमीटर —तदैव—	01 03	5,64,264=00 56,00,000=00	5.64 1,68,00.0
	—तदैव—	04	6,400=00 (प्रतिवर्ग मीटर)	1,47,25.7
	889.875 / 457.50 / 493.02 / 460.50 आफिस हेतु भूखण्ड 20.034 वर्ग मीटर	24	1,28,218=00	30,77,232

408

--तदैव--	02	1,82,309=00	3,64,618=00
स्पेयर पार्ट शाप	24	1,28,218=00	30,77,232=00
20.034 वर्ग मीटर			
--तदैव--	01	1,82,310=00	1,82,310=00
--तदैव--	04	2,37,003=00	9,48,012=00
			<u>योग:- 24,69,31,536</u>
			का 10 प्रतिशत
			₹ <u>2,46,93,154=00</u>

लेखा परीक्षा संस्तुति:- आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.1998 द्वारा अवस्थापना विकास निधि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे। प्राधिकरण में अवस्थापना विकास समिति द्वारा उक्त शासनादेश को लागू नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अधिभार लिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 19

5208

अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी वादों की स्थिति:- मार्च, 2013 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण में अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी 2070 वाद लम्बित थे। इतनी बड़ी संख्या में वाद लम्बित रहना प्राधिकरण हितों के विपरीत था।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्राधिकरण की समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.2013 में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 20

521167

विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान ₹ 7,01,481=00:- श्री आनन्द राम आर्या, अवर अभियन्ता की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि आवास विभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्य- 3534/V/आ0-2006-08(आ0)/2005 दिनांक 22.12.06 द्वारा

श्री आर्या को तात्कालिक प्रभाव से अवर अभियन्ता पद पर विनियमित किया गया था। 01.01.2006 को वेतनमान 4500-125-7000 में मूल वेतन 6500=00 पा रहे थे, जिसे शासनादेश संख्या-2293/V-आ-06-146(आ)/2006 दिनांक 27.04.2007 द्वारा दिनांक 21.08.2007 को वेतनमान 5000-150-8000 में उच्चिकृत किया गया था। श्री आर्या की वेतनवृद्धि तिथि थी। आवास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या- 268/V-आ-2007(आ0)/05 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-560/दस-45(एम0)-99 दिनांक 02.12.01 के अनुरूप समयमान वेतनमान व्यवस्था विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने पर श्री आर्या को 14 वर्ष की सेवा पर 01.03.2002 से प्रथम प्रोन्नत वेतनमान 8000-275-13200 स्वीकृत करते हुए वेतन निर्धारित किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.01 के प्रस्तर 1(2) के अनुसार 14 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान तभी देय था जबकि सम्बन्धित पद पर कर्मचारी नियमित हो चुका हो। स्थिति में श्री आर्या को नियमितीकरण की तिथि से पूर्व प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं था। प्रकार श्री आर्या को विनियमितीकरण की तिथि से पूर्व अनियमित रूप से प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप माह दिसम्बर, 2012 तक संलग्न विवरणानुसार ₹ 7,01,48 अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- अधिक भुगतान की वसूली अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- अप्राप्त।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक:- 21

12/11/12

अशोक कुमार तुम्बडिया के अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में:-माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2011 में दो सप्ताह के भीतर श्री अशोक कुमार तुम्बडिया के अशमनीय भाग को ध्वस्त करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुषंग में विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण हेतु ₹ 6,20,720=00 का व्यय किया गया था। जिसे प्रतिपूर्ति श्री अशोक तुम्बडिया से नहीं कराई गई थी।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- स्थिति स्पष्ट कराई जाये अन्यथा प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- अप्राप्त।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

आपत्ति क्रमांक- 22

वित्तीय स्थिति:- आलोच्य अवधि में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी:-

लेखा

	2011-12	2012-13
01 अप्रैल का प्रतिशेष	32,39,94,469=00	40,37,58,539=00
वर्ष की आय	19,52,62,210=50	20,69,33,424=79
योग	51,92,56,679=95	61,06,91,964=04
वर्ष का व्यय	11,54,98,140=70	13,68,39,279=84
31 मार्च को इतिशेष	40,37,58,539=25	47,38,52,684=20

जोड़िए:-

(1) बिना भुने चैको की राशि	19,13,921=00	16,79,827=00
(2) विगत वर्षों का बैंक समाधान अन्तर	49,312=00	49,312=00

घटाइए:-

(1) बैंक संग्रह हेतु जमा परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं	2,05,842=00	---
(2) विगत वर्षों का बैंक समाधान अन्तर	---	---
(3) बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण डेबिट	4,407=00	2,800=00
31 मार्च को वास्तविक शेष	40,55,11,523=25	47,55,79,023=20

बैंक शेष का विवरण:-

1- सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता सं० 8000 / 1577844296	2,94,80,927=58	3,03,12,072=58
2- ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं० 386 / 52452040000010	5,79,21,563=73	6,13,65,954=61
3- भारतीय स्टेट बैंक खाता सं०-11137	9,22,387=82	9,59,754=82
4- इलाहाबाद बैंक खाता सं० 20342084711	2,11,093=28	2,19,622=28
5- विजया बैंक खाता सं० 451	7,48,82,982=25	10,42,555=04
6- एक्सिस बैंक खाता सं० 25513	2,65,60,580=50	5,91,73,601=78
7- एक्सिस बैंक (F)	51,04,200=00	-
8- पंजाब नेशनल बैंक खाता सं० 137608	3,36,85,767=10	4,85,10,319=10
9- ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं०-08	68,32,608=41	28,67,837=41
10- बैंक आफ इण्डिया खाता सं०-3710	-	5,12,20,760=00
1- पी०एल०ए०	99,06,545=58	99,06,545=58
2- पंजाब नेशनल बैंक 57382	2,867=00	-
3- सावधि जमा	16,00,00,000=00	21,00,00,000=00
<b>योग-</b>	<b>40,55,11,523=25</b>	<b>47,55,79,023=20</b>

टिप्पणी:-

- (1) रोकड़ बही लेजर किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थीं।
- (2) रोकड़ बही के शेष सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थीं।
- (3) पी0एल0ए0 की पासबुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इसके अवशेष का सत्यापन नहीं हो सका।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकृत बैलेन्सशीट तैयार होने पर कौशबुक लेजर पर सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षर करा जायेंगे।

पी0एल0ए0 खाता मेलाधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अतः उसकी पास बुक कार्यालय में उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-

20/10/21

आपत्ति क्रमांक- 23

राजकीय अनुदान:- प्रमाणित किया जाता है कि प्राधिकरण को आलोच्य अवधि में प्राप्त राजकीय अनुदानों का उपयोग, निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्ही उद्देश्यों हेतु किया गया जिनके लिए वे स्वीकृत थे, विचलन की दशा में उसका उल्लेख सम्परीक्षा टिप्पणी में यथासंभव कर दिया गया है।

राजकीय अनुदानों के प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की स्थिति संलग्न प्रपत्र- '66' में दी है।

टिप्पणी:- (1) अनुदान पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

(2) आई0डी0एस0एम0डी0 के अनुदान की राशि लम्बी अवधि से अवशेष चली आ रही सम्बन्धित पत्रावलियां सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही। अवशेष राशि को यथाशघ्न शासन को सौंपा किया जाना अपेक्षित है।

(3) कुम्भ मेला अनुदान की अवशेष राशि शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का कार्यवाही कर ली जायेगी।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-



आपत्ति क्रमांक- 24

सम्परीक्षा शुल्क:- वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की सकल आय क्रमशः ₹ 19,52,62,211=00 एवं ₹ 20,69,33,425=00 पर क्रमशः ₹ 5,86,310=00 एवं ₹ 6,21,320=00 कुल ₹ 12,07,630=00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया। इसे राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुति:- आरोपित सम्परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तर:- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सम्परीक्षा शुल्क वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट मद में प्राविधान के अनुसार जमा करा दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना-लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा-लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक-आपत्ति क्रमांक- 25

राजकीय ऋण:- आलोच्य अवधि में प्राधिकरण को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं था एवं न ही गत वर्षों का कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष था।

आपत्ति क्रमांक- 26

विनियोजन:- आलोच्य अवधि के अन्त में ₹ 21 करोड़ निम्न विवरणानुसार विनियोजित थे:-

सावधि जमा रसीद सं०/दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि	परिपक्वता तिथि
184723 / 29.04.12	विजया बैंक	10,00,00,000=00	29.04.13
184912 / 11.09.12	विजया बैंक	2,50,00,000=00	16.10.13
184911 / 11.09.12	विजया बैंक	2,50,00,000=00	16.10.12
867889 / 11.09.12	यूनियन बैंक	5,00,00,000=00	11.09.13
196350 / 07.11.12	यूनियन बैंक	1,00,00,000=00	07.11.13
	योग:-	21,00,00,000=00	

अनुच्छेद-4

लेखा-परीक्षा की सीमाएं

उदाहरणार्थ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, लेखा-परीक्षकों की पहुंच नहीं रही :-

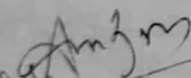
चैक संख्या- 62362 दिनांक 19.01.2012 ₹ 1,45,76,852=00 का भुगतान भल्ला कालेज स्टेडि निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को किया गया था, सम्बन्धित पत्रावली, माप पुस्तिका इत्यादि अभिलेखों की जांच सम्परीक्षा में नहीं की जा सकी।

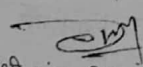
अनुच्छेद-5

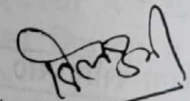
लेखा-परीक्षा संस्तुतियां

लेखा-परीक्षा समीक्षा के दौरान चिन्हित प्रक्रिया संबंधी कमियों, अंतरालों अभिमतो के संबंध में सुधार हेतु सुझाव :-

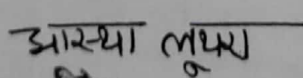
- (1) प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत किसी भूखण्ड विशेष पर या किसी भवन विशेष का मानचित्र प्राधिकरण स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पास कोई पारदर्शी विवरण उपलब्ध था, और न, ही इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई थी।
- (2) अनाधिकृत निर्माण को प्रारम्भिक स्तर पर रोकन हेतु ठोस नीति का अभाव परिलक्षित हुआ।
- (3) अनाधिकृत निर्माण के शमन प्रकरणों में प्रकाश में आया कि अधिकांश शमन स्वीकृत आदेश सम्बन्ध से शपथ पत्र प्राप्त कर निर्गत किये गये थे, शपथ पत्र के अनुसार शपथ कर्त्ता ने अशमनीय निर्माण ध्वस्त किया अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई आख्या पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी।

  
(श्री महोप कुमार सिंह)  
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

  
(श्री गंगा सिंह रावत)  
सहायक लेखा परीक्षक

  
(डॉ० विजय लक्ष्मी)  
जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार  
एवं टीम लीडर, पार्टी सं०-3

प्रतिहस्ताक्षरित

  
डा.अंशु कुमार  
विभागाध्यक्ष  
ऑडिट उत्तराखण्ड  
देहरादून

405

404

प्रेषक,  
उपनिदेशक,  
कोषागार एवं वित्त सेवायें,  
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)  
देहरादून उत्तराखण्ड

सेवा में,  
उपाध्यक्ष/सचिव,  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

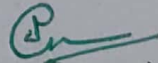
दिनांक: 06 जून 2012

विषय: आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 4353, दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियों का निस्तारण किया जाता है।


वर्ष	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	आपत्तियों की संख्या
2009-10 से 2010-11	1(4),(6)(क)(ख)(ग)(घ),(7),(8),(9),(10), (11),(12),(13),(14),(16),(17),(18),(19), (20),(21),(22),(23),(24),(25),(26), (30)(क)(ख),(31),(32),(33),(34),(35), (36),(37),(38),(39),(40),(41),(42),(43), 8(1),(2),(3),(4).	—	43
		योग	43

  
(के0एन0 दुमका)  
उप निदेशक

कोषागार एवं वित्त सेवायें,  
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग),  
देहरादून उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि:-

1. जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ।

  
(के0एन0 दुमका)  
उप निदेशक